जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार।
निकट देवपुरा चौक, पुरानी कचहरी, हरिद्वार।
E-mail: suchnaharidwar@gmail.comदूरभाष : 01334–226695, मोबाइलः 7055007017

दिनांक : 05.12.2017

प्रेस विज्ञप्ति

हरिद्वार। नीति आयोग की ओर से ''विजन–2022'' हेतु जनपद हरिद्वार के लिए नियुक्त की गयी प्रभारी भारत सरकार की ज्वाइन्ट सेक्रेटरी ज्योत्सना सिटलिंग ने आज कलक्ट्रेट सभागार में विजन–2022 के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश देने के साथ ही गत 05 वर्षों में जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त की गयी उपलब्धियों एवं अगले 05 वर्षों हेतु बनायी कार्ययोजनाओं का प्रोजेक्टर के माध्यम से निरीक्षण किया।

जनपद की गत 05 वर्षों की उपलब्धियों एवं विभन्न विभागों द्वारा अगले 05 वर्षों हेतु बनायी गयी कार्ययोजनाओं के निरीक्षण के दौरान सुश्री ज्योत्सना ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर के साथ ही विभागों द्वारा भी सब कमेटी का गठन कर लिया जाय तथा गहनता से विचार विमर्श कर 01 वर्षीय एवं 05 वर्षीय योजना बनाकर प्रस्तुत की जाय ताकि योजना को नीति आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिये कि जनपद में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं कृषि कार्यों को अधिक महत्व दिया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं से भी नीति आयोग को अवगत कराया जाय। उन्होंनें अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें तभी जनपद समग्र विकास की ओर अग्रसर होगा।

इस दौरान सुश्री ज्योत्सना द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने विजन–2022 के अन्तर्गत देश के ऐसे 115 जिलों का चयन किया है जो सामाजिक और आर्थिक रुप से अत्यन्त पिछड़े हैं। इन जनपदों में अमीरी और गरीबी का गेप बहुत अधिक है। भारत सरकार का उद्देश्य इन जनपदों को 2022 तक समग्र विकास की ओर ले जाना तथा इन जनपदों में बहुत अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच के अन्तर को कम करना है। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में 02 जनपदों हरिद्वार एवं उधमसिहंनगर का चयन विजन–2022 के लिए किया गया है। विजन–2022 के अन्तर्गत उत्तराख्ण्ड के लिए स्टेट प्रभारी अपर सचिव नियोजन डॉ0 रंजीत सिन्हा को नियुक्त किया गया है। सुश्री ज्योत्सना ने बताया कि नीति आयोग द्वारा देश में चयनित 115 जिलों के विकास कार्यों का मूल्यांकन किसी तीसरी पार्टी के माध्यम से हर वर्ष कराया जायेगा ताकि पता चल सके कि कौन सा जनपद किस क्षेत्र में कितना विकास कर रहा है।

बैठक में जिलाधिकारी दीपक रावत द्वारा जनपद की विभिन्न समस्याओं के साथ ही विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा मेनपावर की समस्या को जनपद की प्रमुख समस्या बताया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विशेष रुप से स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अभाव में जनपद में स्वास्थ्य योजनाएं प्रभावित होती हैं। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे कार्ययोजना के साथ ही विभागों से जुडी फण्ड, मेनपावर, मशीनरी आदि की डिमाण्ड जो भारत सरकार द्वारा पूरी की जा सकती है से भी नीति आयोग को अवगत करायें।

बैठक मं अपर सचिव नियोजन डॉ0 रंजीत सिन्हा, अपर सचिव ग्रामीण विकास वाईके पन्त, सीडीओ स्वाति भदौरिया, पीडी संजीव राय, डीडीओ पुष्पेन्द्र चौहान, सीएमओ अशोक कुमार गैरौला, जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार।